



डरने की जरूरत नहीं ।

मित्रों नमस्कार 15.10.2014

मेरे यह समझ मे नहीं आ रहा है कि आप लोग लोगों को क्या शिक्षा देते होगें । जब आप सही और गलत को समझ नहीं पाते हो । जब आपको मालूम है कि फीस कमेटी गलत ऑकडे प्रस्तुत कर रही है तो भी आप फीस कमेटी के हर ऑकडे पर विश्वास कर फोन कर देते हो । अब क्या करे ।

यदि आपको डर लग रहा है और लगता है कि पोर्टल भरने से आपका स्कूल चल जायेगा तो भर दीजिए –

लेकिन इन ऑकडो पर गौर जरूर कीजिए –

1. राजस्थान मे शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर 2013 तक मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 43988 बता रखी है ।
2. 2012 मे आरटीई पोर्टल पर 37500 स्कूलों ने पंजीकरण करवाया था
3. इस वर्ष केवल 32000 के करीब स्कूलों ने ही पोर्टल पर पंजीकरण करवाया तो क्या बाकी स्कूल – स्कूल नहीं । क्या उनकी फीस तय नहीं होगी ? ?
4. 14.10.2014 तक 19748 ने लॉक किया था जो कि 10.10.14 के 18248 ऑकडे से 1500 ज्यादा हुआ । तो डरने की क्या बात है ।
5. रही बात आज की अखबार की खबर की तो – फीस कमेटी के अनुसार 5000 के करीब स्कूलों ने सहमति भी दे दी एक दिन मे क्योंकि 14.10.2014 को तो फीस कमेटी ने ऐसा नहीं लिखा था ।

6. यदि केवल पाँच हजार स्कूल ही बचे हैं तो पोर्टल क्यों चालु रखा है फीस कमेटी ने ?
7. डरपोक लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता । सरकार भी यह जानती है इसीलिए पोर्टल को चालू रखे हुए है ।

हम उन लोगों को गारन्टी देते हैं जो हमारे साथ है अर्थात् पोर्टल नहीं भर रहे हैं । कि उनका कोई कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता । फीस कमेटी जिस कोर्ट की बात आज कह रही है उसके बारे में मैंने आपको 9.10.14 को ही बता दिया था । फिर भी आप डर रहे हैं तो डरे ।

हमने उस कोर्ट में केवियट लगा दी है जिसमें फीस कमेटी सूची पेश करेगी । अर्थात् वह कोर्ट हमें सुनें बिना फीस कमेटी को कोई निर्णय नहीं देगा । तो डरने की बात ही नहीं । भरने का चॉस तो आपको कोर्ट भी दे देगा ।

रही बात नुकसान की तो जिन्होंने भरा है यदि उनके साथ फीस कमेटी न्याय करती है तो हम भी भर देगें । यदि अन्याय करती है तो वे भी आपके साथ आ जायेंगे । ओर हमें अपनी कागजी कार्यवाही का मौका भी मिल जायेगा ।

अतः नहीं भरने वाले का तो फायदा ही है । बाकी आपकी मर्जी

अनिल शर्मा